



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-12] रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 जुलाई, 2011 ई0 (श्रावण 08, 1933 शक सम्वत्) [संख्या-31

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्द्रा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	3075
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	297-317	1500
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	279-282	1500
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	35-38	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्वेज-स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सिंचाई विभाग

विज्ञप्ति/पदोन्नति

25 अप्रैल, 2011 ई०

संख्या 1094/II-2010-01(440)/2003-श्री महेन्द्र सिंह यादव, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग को श्री रोमेश कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता (सिविल) की दिनांक 30-04-2011 को सेवानिवृत्ति के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान ₹ 15600-39100 सदृश ग्रेड वेतन ₹ 6600 में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-उक्त पदोन्नति आदेश मा० न्यायालयों में योजित याचिकाओं के निर्णयाधीन रहेंगे तथा वरिष्ठ कार्मिक के पात्र होने और रिक्ति उपलब्ध न होने तथा वरिष्ठता क्रम में कनिष्ठ होने की स्थिति में श्री महेन्द्र सिंह यादव को सहायक अभियन्ता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

3-श्री महेन्द्र सिंह यादव की पदस्थापना के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,

पी० सी० शर्मा,
प्रमुख सचिव।

कार्मिक अनुभाग-1

विज्ञप्ति/त्याग-पत्र

28 अप्रैल, 2011 ई०

संख्या 595/तीस-1-2011-26(07)/2011-श्री अशोक कुमार मान, अति० सिविल जज (जूनियर डिविजन) प्रथम, देहरादून के पत्र दिनांक 20-04-2011 में उनके द्वारा किये गये अनुरोध एवं महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1813/XIV-a-12/Admin.A/2009, दिनांक 22 अप्रैल, 2011 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय श्री अशोक कुमार मान, अति० सिविल जज (जूनियर डिविजन) प्रथम, देहरादून का त्याग-पत्र तात्कालिक प्रभाव से स्वीकार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

28 अप्रैल, 2011 ई०

संख्या 618/तीस-1-2011-26(08)/2011-श्री सुनील कुमार, अति० जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रुद्रपुर (III F.T.C.) जनपद ऊधमसिंह नगर के पत्र दिनांक 21-04-2011 में उनके द्वारा किये गये अनुरोध एवं महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1837/XIV-a-29/Admin.A/2010, दिनांक 25 अप्रैल, 2011 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय श्री सुनील कुमार, अति० जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रुद्रपुर (III F.T.C.) जनपद ऊधमसिंह नगर का त्याग-पत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

गृह विभाग

अधिसूचना

16 मई, 2011 ई0

संख्या 640/XX-2/56/सुरक्षा/2007-श्री राज्यपाल, निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन), अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या-29, वर्ष 2005) की धारा-3 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके "निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए राज्य की आदर्श नियमावली, 2009" के प्रयोजन हेतु श्री रविनाथ रामन, अपर सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन को 'नियंत्रक प्राधिकारी' नामित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 1588/XX-2/56/सुरक्षा/2007, दिनांक 14 दिसम्बर, 2009 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से,

राजीव गुप्ता,

प्रमुख सचिव, गृह।

कार्मिक अनुभाग-1

प्रोन्नति

विज्ञप्ति

27 मई, 2011 ई0

संख्या 752/XXX-1-11-25(4)/2008-उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के उच्चतर वेतनमान रु0 37,400-67,000 ग्रेड पे 8,900/- में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को श्री राज्यपाल महोदय, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान पद पर ही उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) उच्चतम वेतनमान रु0 37,400-67,000 + ग्रेड पे 10,000/- में पदोन्नति करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्रम सं0

नाम अधिकारी

1. श्री प्रदीप मुलासी
2. श्री सतीश चन्द्र बडोनी
3. श्री उमेश चन्द्र कबड़वाल
4. श्री मदन सिंह कुण्डरा।

27 मई, 2011 ई0

संख्या 753/XXX-1-11-25(4)/2008-उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के विशेष वेतनमान रु0 37,400-67,000 ग्रेड पे 8,700/- में कार्यरत श्री इन्दुधर को श्री राज्यपाल महोदय, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान पद पर ही उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) उच्चतम वेतन रु0 37,400-67,000 + ग्रेड पे 8,900/- में पदोन्नति करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

27 मई, 2011 ई0

संख्या 754/XXX-1-11-25(4)/2008-उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के उच्चतम वेतनमान रु0 37,400-67,000 ग्रेड पे 10,000/- में कार्यरत श्री कुँवर सिंह को श्री राज्यपाल महोदय, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान पद पर ही उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) विशेष उच्चतम वेतन रु0 67,000-79,000 (03 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) में पदोन्नति करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

पेयजल अनुभाग-1

नियुक्ति

विज्ञप्ति

03 जून, 2011 ई0

संख्या 661/उन्तीस(1)/2011-(36 अधि0)/2005-उत्तराखण्ड राज्य अभियन्त्रण सेवा परीक्षा, 2007 के आधार पर सम्यक् रूप से चयनित/संस्तुत अभ्यर्थियों की संस्तुतियां लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 50/03/ई0-1/2004-05, दिनांक 05 अप्रैल, 2011 तदक्रम में कार्मिक, विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 517/XXX(2)/2011, दिनांक 13 अप्रैल, 2011 द्वारा शासन को उपलब्ध कराई गई है। लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभ्यर्थियों की उपरोक्त संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में श्री राज्यपाल महोदय अधोलिखित अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य परीक्षा राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड द्वारा कराये जाने के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर उत्तराखण्ड जल संस्थान में सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के पद वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड पे ₹ 5400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की परीवीक्षा पर अस्थाई रूप से नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र0सं0	नाम	पिता का नाम	सिविल/विद्युत यांत्रिक	तैनाती का स्थान
1	2	3	4	5
1.	सर्व श्री सन्तोष कुमार उपाध्याय	श्री पीताम्बर उपाध्याय	सिविल	पित्थूवाला, देहरादून
2.	" " मनीष सेमवाल	श्री मोहन लाल सेमवाल	सिविल	हरिद्वार
3.	" " मदन मोहन शर्मा	स्व0 श्री जयन्ती प्रसाद शर्मा	सिविल	पौड़ी
4.	" " सुनील तिवारी	स्व0 श्री जे0एन0 तिवारी	सिविल	रामनगर
5.	" " विनोद चन्द्र रमोला	श्री नाग चन्द्र रमोला	सिविल	मसूरी
6.	" " विशाल कुमार	श्री आनन्द स्वरूप सक्सेना	सिविल	चम्पावत
7.	" " नमित रमोला	श्री भरत चन्द्र रमोला	सिविल	टिहरी
8.	" " बलदेव सिंह	श्री जगदीश सिंह	सिविल	अनुरक्षण खण्ड, देहरादून
9.	" " सतेन्द्र कुमार गुप्ता	श्री रवीन्द्र कुमार	सिविल	नैनीताल
10.	" " रमेश चन्द्र	स्व0 श्री गंगा राम आर्य	सिविल	नैनीताल
11.	" " राजीव सैनी	श्री प्रकाश चन्द्र सैनी	सिविल	पौड़ी
12.	" " यशवीर मल्ल	स्व0 श्री अमर बहादुर मल्ल	सिविल	डीडीहाट
13.	" " बिलाल युनूस	श्री मोहम्मद युनूस	सिविल	अल्मोड़ा
14.	" " मोनिका वर्मा	स्व0 श्री ओम प्रकाश	सिविल	अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय नगर, देहरादून
15.	" " मनीष बिष्ट	श्री कुन्दन सिंह बिष्ट	विद्युत/यांत्रिक	पिथौरागढ़
16.	" " भरत प्रकाश सिंह	श्री बच्ची सिंह रावत	विद्युत/यांत्रिक	दक्षिण देहरादून
17.	" " प्रियदर्शन सिंह रावत	श्री विजेन्द्र सिंह रावत	विद्युत/यांत्रिक	बागेश्वर
18.	" " नन्द किशोर	श्री दीवानी राम	विद्युत/यांत्रिक	अल्मोड़ा
19.	" " सुशील कुमार सैनी	श्री दया राम सैनी	विद्युत/यांत्रिक	रानीखेत
20.	" " प्रवीन कुमार	श्री जयचन्द	विद्युत/यांत्रिक	रुद्रप्रयाग

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतया: औपबन्धिक एवं अस्थाई हैं तथा अभ्यर्थियों के चरित्र, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण-पत्र एवं प्रागवृत्त सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी। इस सम्बन्ध में वे किसी भी मा0 न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे।
3. ये नियुक्तियां मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 297 ऑफ 2010 सतीश चन्द्र नौटियाल एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम आदेशों के अधीन होगी।
4. सम्बन्धित अभ्यर्थी दिनांक 15 जून, 2011 तक मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नेहरू कॉलोनी, देहरादून के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। मुख्य महाप्रबन्धक के कार्यालय में उन्हें अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा तदपश्चात् मुख्य महाप्रबन्धक उन्हें तैनाती के स्थान हेतु कार्यमुक्त करेंगे।
5. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी अपने स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल/अचल सम्पत्ति का विवरण तथा एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का घोषणा-पत्र/शपथ-पत्र अवश्य उपलब्ध करायेंगे।
6. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-
 क- शैक्षिक योग्यता, आयु, बी0ई0 डिग्री एवं जाति प्रमाण-पत्र की दो प्रमाणित प्रतियां (किसी राजपत्रित अधिकारी से)।
 ख- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सक्रिय सेवा में हो और उनकी निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र-प्रमाण-पत्र।
 ग- लिखित रूप से एक अण्डर टेकिंग कि यदि चरित्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं प्रागवृत्त के सत्यापन में उन्हें सरकारी सेवा में उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता देय नहीं होगा।

आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग

अधिसूचना

07 जून, 2011 ई0

संख्या 541/VIII/11-479(क0रा0बी0यो0)/2003-राज्यपाल, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 34, वर्ष 1948) की धारा 1 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करके तथा केन्द्र सरकार के अनुमोदन से इस अधिनियम के उपबन्धों का निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थापनों के वर्गों पर विस्तार की, इस आशय की एक मास की सूचना अधिसूचना संख्या 2542/VIII/10-497 (क0रा0बी0यो0)/2003, दिनांक 27 जनवरी, 2011 द्वारा शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के उपरान्त एवं इस विषय में निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त न होने के पश्चात् सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

अनुसूची

स्थापनों का विवरण

वे क्षेत्र जहाँ स्थापन स्थित हैं

1

2

निम्नलिखित स्थापन, जिनमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं अथवा पिछले बारह महीनों में किसी दिन नियोजित थे :-

उत्तराखण्ड राज्य के वे सभी क्षेत्र जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के प्राविधान अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पहले से लागू किये जा चुके हैं।

- (क) दुकान;
 (ख) होटल;
 (ग) रेस्तरा;
 (घ) सड़क मोटर परिवहन स्थापन;
 (ङ) पूर्वदर्शन थियेटर सहित सिनेमाघर;
 (च) कामकाजी पत्रकार तथा अन्य समाचार-पत्र कर्मकार (सेवा की शर्तें) तथा प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 2 (घ) में यथा परिभाषित समाचार-पत्र स्थापन;
 (छ) व्यक्तियों, न्यासियों, सोसाइटियों अथवा संगठनों द्वारा चलाये जाने वाले शैक्षिक संस्थान (सार्वजनिक, निजी सहायता प्राप्त अथवा आंशिक सहायता प्राप्त सहित);
 (ज) चिकित्सा संस्थान (निगमित, संयुक्त क्षेत्र, न्यास, धर्मार्थ तथा निजी स्वामित्व वाले अस्पताल, नर्सिंग होम, निदान केन्द्र, रोग विज्ञान प्रयोगशाला)।

आज्ञा से,

विनीता कुमार
 प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 541/VIII/11-479(ESI)/2003, dated June 07, 2011 for general information :

NOTIFICATION

June 07, 2011

No. 541/VIII/11-479(ESI)/2003--In exercise of the powers Conferred by Sub-Section (5) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (Central Act No. 34 of 1948), the Governor, in consultation with the Employees' State Insurance Corporation and with the approval of the Central Government and after giving notice of its intention vide Notification No. 2542/VIII/10-497(ESI)/2003, dated January 27, 2011 in the Official Gazette and after receiving no objection or suggestion on the subject, is pleased to extend the provisions of the Act to the classes of establishments specified in the schedule given below :--

SCHEDULE

Description of establishments	Areas in which the establishments are situated
1	2
Following establishments wherein ten or more persons are employed, or were employed on any day of the preceding twelve months :-	All areas in the State of Uttarakhand where the provisions of the ESI Act, 1948 have already been brought into force under Sub-Section (3) of Section 1 of the Act.
a) Shops;	
b) Hotels;	
c) Restaurants	

- (e) Cinemas including preview theatres;
- (f) Newspaper Establishments as defined in Section 2(d) of the Working Journalists and other Newspaper Employees' (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955)
- (g) Educational Institutions (including public, private, aided or partially aided) run by individuals, trustees, societies or other organizations;
- (h) Medical Institutions (including corporate, joint sector, trust, charitable and private ownership hospitals, nursing homes, diagnostic centers, pathological labs).

By Order,

VINITA KUMAR,
Principal Secretary.

सिंचाई विभाग

विज्ञप्ति/पदोन्नति

20 जून, 2011 ई0

संख्या 1589/II-2011-01(440)/2003-श्री अवधेश राम, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग को श्री शिव दयाल भास्कर, अधिशासी अभियन्ता (सिविल) की दिनांक 30-06-2011 को सेवानिवृत्ति के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान ₹ 15600-39100 सदृश ग्रेड वेतन ₹ 6600 में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नति आदेश मा0 न्यायालयों में योजित याचिकाओं के निर्णयाधीन रहेंगे तथा वरिष्ठ कार्मिक के पात्र होने और रिक्ति उपलब्ध न होने तथा वरिष्ठता क्रम में कनिष्ठ होने की स्थिति में श्री अवधेश राम को सहायक अभियन्ता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

3. श्री अवधेश राम की पदस्थापना के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

22 जून, 2011 ई0

संख्या 1443/II-2011-01(162)/2003-कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) के सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पदों पर नियमित चयन द्वारा प्रोन्नति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 505/21/डी0पी0.सी0/2010-11, दिनांक 25-05-2011 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) को सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) वेतनमान रु0 15600-39100 एवं सदृश ग्रेड पे रु0 5400 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

डिप्लोमाधारी संवर्ग-

1. श्री चरण दत्त,
2. श्री सूर्य प्रकाश वाष्णीय,
3. श्री कृष्ण अग्रवाल,
4. श्री एस0एन0 पाण्डे।

उक्त पदोन्नति आदेश सम्बन्धित रिट याचिकाओं में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम आदेशों के अधीन रहेंगे। पदोन्नत कार्मिकों को वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनके पद स्थापना आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,

पी0 सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

अधिसूचना

23 जून, 2011 ई0

संख्या 815/VIII/11-43-श्रम/2010-राज्यपाल, बंधित श्रम पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 19, सन् 1976) की धारा 13 की उप-धारा (1) और (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त पूर्व में जारी अधिसूचना का अतिक्रमण करते हुए जिला पौड़ी गढ़वाल के परगना श्रीनगर के लिए सतर्कता समिति का निम्नवत् गठन करते हैं, अर्थात्—

क्र० सं०	धारा	नाम/पदनाम एवं पता	समिति के पदनाम
1.	13(3)(ए)	उप जिलाधिकारी, श्रीनगर	अध्यक्ष
2.	13(3)(बी)	श्री दर्शन सिंह पुत्र श्री बगोलिया, ग्राम श्रीकोट, गंगानाली, श्रीनगर	सदस्य (अनु०जा०/जनजाति)
3.		श्री हर्ष लाल पुत्र श्री नीरतु लाल, ग्राम सुमाड़ी, पो० सुमाड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल	सदस्य (अनु०जा०/जनजाति)
4.		श्री शिव प्रसाद पुत्र श्री मोहन लाल (पूर्व ग्राम प्रधान) ग्राम देवलगढ़, बुधाड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल	सदस्य (अनु०जा०/जनजाति)
5.	13(3)(सी)	श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री नत्थी सिंह ग्राम पुराना श्रीनगर, कमलेश्वर	सदस्य (सामाजिक कार्यकर्ता)
6.		श्री सूरज घिल्डियाल पुत्र श्री राजेश घिल्डियाल, ग्राम डांग, पो०आ० डांग, कमलेश्वर बायां श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल	सदस्य (सामाजिक कार्यकर्ता)
7.	13(3)(डी)	खण्ड विकास अधिकारी, खिसू	सदस्य (ग्राम विकास से सम्बन्धित राजकीय सेवक)
8.		सहायक खण्ड विकास अधिकारी, खिसू	सदस्य (ग्राम विकास से सम्बन्धित राजकीय सेवक)
9.		ग्राम पंचायत अधिकारी/बहुउद्देशीय कर्मचारी, ग्राम सभा श्रीकोट, गंगानाली, श्रीनगर	सदस्य (ग्राम विकास से सम्बन्धित राजकीय सेवक)
10.	13(3)(ई)	प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, श्रीनगर	सदस्य (वित्त एवं ऋण संस्थान के प्रतिनिधि)
11.	13(3)(एफ)	तहसीलदार, श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल।	सदस्य (धारा-10 के अन्तर्गत परगना में कार्यरत विनिर्दिष्ट अधिकारी)

आज्ञा से,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 815/VIII/11-43-Shram/2010, dated June 23, 2011 for general information :

NOTIFICATION

June 23, 2011

No. 815/VIII/11-43-Shram/2010—In exercise of the powers Conferred by Sub-Section (1) and (3) of Section 13 of the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 (Central Act No. 19 of 1976) and in super-session of all the previous notifications on the subject, the Governor is pleased to constitute Vigilance Committee for **Sub-division Shrinagar District of Pauri Garhwal** as follows; namely :--

Sl.No.	Section	Name/Designation & Address	Designation in Committee
1.	13(3)(a)	Sub-divisional Magistrate, Shrinagar	Chairman
2.	13(3)(b)	Mr. Darshan Lal S/o Mr. Bagoliya, Village-Srikot, Ganganali, Srinagar	Member (SC/ST)
3.		Mr. Harsh Lal S/o Mr. Neertu Lal, Village & Post Sumadi, Pauri Garhwal	Member (SC/ST)
4.		Mr. Shiv Prasad S/o Mr. Mohan Lal (Ex Gram Pradhan), Village-Devalgarh, Bughari, Pauri Garhwal	Member (SC/ST)
5.	13(3)(c)	Mr. Virendra Singh S/o Mr. Natthi Singh, Village-Purana, Srinagar, Kamleshwar	Member (Social Worker)
6.		Mr. Suraj Ghildiyal S/o Mr. Rajesh Ghildiyal, Village-Daang, P.O.Daang, Kamleshwar Via Srinagar, Pauri Garhwal	Member (Social Worker)
7.	13(3)(d)	BDO, Khirsu	Member (Official/Non Off. Connected with Rural Development)
8.		ADO, Khirsu	Member (Official/Non Off. Connected with Rural Development)
9.		Gram Panchayat Adhikari/Bahu-uddesiya Armchair Gram Sabha, Srikot, Ganganali, Srinagar	Member (Official/Non Off. Connected with Rural Development)
10.	13(3)(e)	Manager, PNB, Srinagar	Member (Representing Financial/Credit Institutions)
11.	13(3)(f)	Tehsildar, Srinagar, Pauri Garhwal.	Member (Officer Specified Under Section 10 and Functioning in the Sub-division)

By Order.

VINITA KUMAR,
Principal Secretary.

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग

अधिसूचना

27 जून, 2011 ई0

संख्या 694/VIII/11-127(श्रम)/2001-राज्यपाल, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 8, वर्ष 1923) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम 10, वर्ष 1897) की धारा 21 (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व अधिसूचना संख्या 1630-औ0वि0/2001-127-श्रम/2001, दिनांक 23-07-2001 एवं संख्या 2702/औ0वि0-2/127-श्रम/2001, दिनांक 04-12-2001 का अधिक्रमण करते हुए, श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी, समस्त अपर/उप श्रम आयुक्तों तथा श्रम आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड, क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत सहायक श्रम आयुक्तों को, जो या तो सीधी भर्ती से या तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त हुए हों और जिन्होंने सहायक श्रम आयुक्त के पद पर पाँच वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, को तथा राज्य के विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियम वर्ष 1923 के अधीन समस्त मामलों के निस्तारण और कर्तव्यों के वहन करने के लिए उनकी अधिकारिता की सीमा के भीतर अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आयुक्त नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 694/VIII/11-127(Shram)/2001, dated June 27, 2011 for general information :

NOTIFICATION

June 27, 2011

No. 694/VIII/11-127(Shram)/2001--In exercise of the powers under the Employees' Compensation Act, 1923 (Central Act No. VIII of 1923), read with section 21 A of the General Clauses Act, 1897 (Central Act No. X of 1897) and in supersession of Government notification no. 1630-Auo.Vi./2001-127-Shram/2001, dated 23-07-2001 and no. 2702/Auo.Vi.-2/127-Shram/2001, dated 04-12-2001, the Governor is pleased to appoint the Labour Commissioner, Uttarakhand, Haldwani, all Additional/Deputy Labour Commissioners and such Assistant Labour Commissioners who are either directly appointed or promoted and who have completed five years service on the post of Assistant Labour Commissioner, posted in the Office of the Labour Commissioner, Uttarakhand, Haldwani or in various Regional and Sub-Regional offices there of and all the District Magistrates of the State as Commissioner for the purpose of discharging duties and disposal of all matters arising under the said Act of 1923 within the local limits of their respective Jurisdictions, from the date of publication of this notification in the Gazette.

By Order,

VINITA KUMAR,
Principal Secretary.

राजस्व अनुभाग-2

विज्ञप्ति

प्रकीर्ण

30 जून, 2011 ई0

संख्या 1015/18(2)/2011-चूँकि, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1954) (समय-समय पर यथासंशोधित तथा उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 53-क के अधीन ग्राम लखोली, तहसील चौबट्टा खाल, जनपद गढ़वाल द्वारा स्वैच्छिक चकबन्दी योजना तैयार करने के लिए प्रस्ताव पारित

केया गया है एवं जिलाधिकारी, गढ़वाल ने उक्त ग्राम में स्वैच्छिक चकबन्दी किए जाने के लिए अपनी संस्तुति अपने पत्र संख्या 1401/7-भू लेख (2010-11), दि0 25-4-2011 द्वारा की है;

और, चूँकि, राज्य सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि उक्त योजना उपर्युक्त अधिनियम के अधीन चकबन्दी के सामान्य सिद्धान्तों के अनुरूप है और ऐसा करना लोक हित में है;

अतएव, राज्यपाल उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके यह आदेश देते हैं कि जनपद गढ़वाल, तहसील चौबट्टा खाल के ग्राम लखोली में इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने की तारीख से स्वैच्छिक चकबन्दी क्रियाएँ आरम्भ करायी जाये।

आज्ञा से,

पी0 सी0 शर्मा,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1015/XVIII(II)/11, dated June 30, 2011 for general information :

MEMORANDUM

Miscellaneous

June 30, 2011

No. 1015/XVIII(II)/11--Whereas, the Village Lakholi, Tehsil Choubatta Khal, District Garhwal have passed a resolution to prepare the voluntary Consolidation of Holdings Scheme under section 53-A of the Uttar Pradesh Consolidation of Holding Act, 1953 (Act No. 5 of 1954) (as amended from time to time and applicable to the State of Uttarakhand) and the Collector, Garhwal has recommended for the voluntary consolidation of the holding in above village vide his letter No. 1401/7-Bhoo-lekh(2010-11), dated 25-4-2011;

And, whereas, the State Government is satisfied that it confirm to the broad principles of consolidation under the act and it is do to so.

Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(a) of section 4 of the said Act, the Governor is pleased to order that the voluntary consolidation of holdings shall be carried out in village Lakholi of Tehsil Choubatta Khal, District Garhwal with effect from the date of publication of this Memorandum.

By Order,

P. C. SHARMA,
Principal Secretary.

न्याय अनुभाग-2

अधिसूचना

प्रकीर्ण

15 जुलाई, 2011 ई0

संख्या 03/XXXVI(2)/2011-112-एक/03-साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-11 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की संस्तुति पर जिला अल्मोड़ा में स्थित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा के न्यायालय को हल्द्वानी, जिला नैनीताल तथा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल के न्यायालय को कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल में स्थानान्तरित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

टी0 पी0 गैरोला,

प्रमुख सचिव।

न्याय अनुभाग-1

अधिसूचना

विविध

15 जुलाई, 2011 ई0

संख्या 128/XXXVI/07-33-एक(4)/04-राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 1976) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 7 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवा की शर्तों) की नियमावली, 1991 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-
उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तों)
(संशोधन) नियमावली, 2011

1-संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार-

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तों) (संशोधन) नियमावली, 2011 है।

(2) यह नियमावली 01 जनवरी, 2006 की तारीख से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

3-नियम 3 का प्रतिस्थापना-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तों) नियमावली, 1991 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त), जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 3 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

3-वेतन-उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तों) (संशोधन) नियमावली, 2009 के प्रवृत्त होने के बाद नियुक्त होने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति का, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हो या जो केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ हो, नियत वेतन ऐसी सेवा निवृत्ति के समय उसे भुगतान किया गया या देय वेतन होगा:

परन्तु यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति जो पेंशन के रूप में सेवानिवृत्ति के किसी लाभ को प्राप्त करता है या प्राप्त किया है, तो उसके उपर्युक्त वेतन से, पेंशन की सकल राशि को, जिसमें व्यक्ति की सरांशीकृत पेंशन का भाग, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, कम कर दिया जायेगा:

परन्तु यह और कि उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तों) (संशोधन) नियमावली, 2009 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व की तिथि पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्यरत व्यक्ति को उसके इस रूप में अवशेष कार्यकाल की अवधि तक उसे तत्समय प्रवृत्त नियमों के अन्तर्गत वेतन से राशिकरण के पूर्व पेंशन घटाकर वेतन मिलता रहेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

3-वेतन-अध्यक्ष नब्बे हजार रुपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त करेगा, उपाध्यक्ष अस्सी हजार रुपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त करेगा और सदस्य रु0 67000 (3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) 79000/- प्रतिमाह वेतन प्राप्त करेगा:

परन्तु यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति का जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हो या जो केन्द्र या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ हो, वेतन ऐसी सेवा निवृत्ति के समय उसे भुगतान किये गये या देय वेतन से कम नहीं होगा:

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो पेंशन के रूप में सेवानिवृत्ति के किसी लाभ को प्राप्त करता है या प्राप्त किया है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है, तो उसके उपर्युक्त वेतन से पेंशन की सकल राशि को, जिसमें व्यक्ति की सरांशीकृत पेंशन का भाग, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, कम कर दिया जायेगा।

नियम-4 का प्रतिस्थापन

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

4- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य केन्द्र सरकार के समूह क के अधिकारियों को अनुमन्य दरों पर अपने वेतन के अनुरूप महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता प्राप्त करेंगे।

3-नियम 11 का प्रतिस्थापन

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

11-(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में अधिकरण में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए राज्य सरकार के सचिव की श्रेणी के अधिकारी को अनुमन्य प्रकार के किराया मुक्त सरकारी आवास की व्यवस्था की जायेगी।

(2) जहाँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवास की व्यवस्था न की जाय या यह स्वयं उसका लाम नहीं उठाता है तो उसे पन्द्रह सौ रुपये प्रतिमाह के भत्ते का भुगतान किया जा सकता है।

(3) जहाँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अनुज्ञेय अवधि के उपरान्त किसी सरकारी आवास का अध्यासन करता है वहाँ वह यथास्थिति, प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार लाइसेंस फीस या शास्तिक किराये का देनदार होगा और उसे बेदखल किया जा सकेगा।

4. मूल नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रखा दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

4-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य केन्द्र सरकार के समूह क के अधिकारियों को अनुमन्य दरों पर अपने वेतन के अनुरूप महंगाई भत्ता और तत्काल प्रभाव से पर्वतीय विकास भत्ता प्राप्त करेंगे।

5-मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम-11 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रखा दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

11-(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में अधिकरण में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए राज्य सरकार के सचिव की श्रेणी के अधिकारी को अनुमन्य प्रकार के किराया मुक्त सरकारी आवास की व्यवस्था की जायेगी।

(2) जहाँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवास की व्यवस्था न की जाय या यह स्वयं उसका लाम नहीं उठाता है तो उसे उसी वेतनमान के राज्य सरकार के कार्मिकों को अनुमन्य दर से आवास किराया भत्ता तत्काल प्रभाव अनुमन्य किया जायेगा। रु0 90,000 के नियत वेतन हेतु भी मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता रु0 80,000 नियत वेतन के बराबर होगी।

(3) जहाँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अनुज्ञेय अवधि के उपरान्त किसी सरकारी आवास का अध्यासन करता है, वहाँ वह यथास्थिति, प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार लाइसेंस फीस या शास्तिक किराये का देनदार होगा और उसे बेदखल किया जा सकेगा।

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 128/XXXVI/2007-33-1(4)/04, dated July 15, 2011 for general information :

NOTIFICATION

Miscellaneous

July 15, 2011

No. 128/XXXVI/2007-33-1(4)/04--In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Uttar Pradesh Public Services Tribunal Act, 1976 (U.P. Act. 17 of 1976), (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Public Services Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1991 (as applicable to the State of Uttarakhand):--

THE UTTARAKHAND PUBLIC SERVICES TRIBUNAL (SALARIES AND ALLOWANCES AND CONDITIONS OF SERVICE OF CHAIRMAN, VICE-CHAIRMAN AND MEMBERS), (AMENDMENT) RULES, 2011.

1. Short Title and Commencement--

(1) The Rules may be called The Uttarakhand Public Services Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members), (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from January 01, 2006.

3. Substitution of Rule-3--

In the Uttar Pradesh Public Services Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members), Rules, 1991 (as applicable to the State of Uttarakhand), hereinafter referred to as principal Rules, for the existing rule 3 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely--

**Column-1
Existing Rule**

3. Salary- The Salary of a person appointed as Chairman, Vice-Chairman or a Member who has retired as a Judge of the High Court of who has retired from Service under the Central or a State Government after the commencement of the Uttarakhand Public Service Tribunal (Salaries & Allowances and conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman or a Members), (Amendment) Rules, 2009 shall be the salary paid or payable to him at the time of such retirement:

Provided that a person appointed as Chairman, Vice-Chairman or a Member who is in receipt of or has received any retirement benefits by way of pension, the aforementioned pay shall be reduced by the gross amount of pension including the commuted portion of his pension, if any:

Provided further that a person servicing as Chairman, Vice-Chairman or a Member on the date immediately before the commencement of the Uttarakhand Public Service Tribunal (Salaries & Allowances and conditions of service of Chairman, Vice-Chairman and Member) (Amendment) Rules, 2009 shall continue to receive pay minus the pension before commutation up to the remaining period of his service as such under the rules in force for the time being.

Substitution of Rule-4

**Column-1
Existing Rule**

4. The Chairman, Vice-Chairman and a Member shall receive dearness allowance and city compensatory allowance appropriate to their pay at the rates admissible a to Group 'A' officers of the Central Government.

Substitution of Rule-11

**Column-2
Rule as hereby substituted**

3. Salary- The Chairman shall receive a pay of Rs. 90,000 per month, Vice-Chairman shall receive a pay of Rs. 80,000 per month and a Member shall receive pay in the pay scale of Rs. 67,000 (annual increment @ of 3%) 79,000 per month:

Provided that the salary of a person, appointed as Chairman, Vice-Chairman or a Member, who has retired as a Judge of the High Court or who has retired from Service under the Central or a State Government, shall not be less than the salary paid or payable to him at the time of such retirement:

Provided further that a person referred to in the first proviso, who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, the aforementioned pay shall be reduced by the gross amount of pension including commuted portion of pension, if any.

4. In the Principal rule for the existing rule 4 set out in column-1 below, the rule set out in column-2 shall be substituted, namely--

**Column-2
Rule as hereby substituted**

4. The Chairman, Vice-Chairman and a Member shall receive dearness allowance and hill development allowance with immediate effect appropriate to their pay at the rates admissible a to Group 'A' officers of the Central Government.

5. In the Principal rule, for the existing rule 11 set out in column-1 below, the rule set out in column-2 substituted, namely--

Column-1
Existing Rule

11. Accommodation- (1) Every person appointed to the tribunal as Chairman, Vice-Chairman or Member shall be provided with an official accommodation of the type admissible to an officer of the rank of a Secretary to the State Government free of rent.

(2) When a Chairman, a Vice-Chairman or a Member is not provided with or does not avail himself of the accommodation referred to in sub rule (i) he may be paid an allowance of Rupees fifteen hundred per month.

(3) Where the Chairman, a Vice-Chairman or a Member occupies an official residence beyond the permissible period he shall be liable to pay license fee or panel rent, as the case may be and liable to eviction in accordance with rules and orders in force.

Column-2
Rule as hereby substituted

11.(1) Every person appointed to the tribunal as Chairman, Vice-Chairman or Member shall be provided with an official accommodation of the type admissible to an officer of the rank of a Secretary to the State Government free of rent.

(2) When a Chairman, a Vice-Chairman or a Member is not provided with or does not avail himself of the accommodation referred to in sub rule (i) he shall be paid such amount of house rent allowance with immediate effect as admissible to the State Government personnel in the same pay scale. Admissibility of house rent allowance in the fixed pay of Rs. 90,000 shall be same as is admissible in the fixed pay of Rs. 80,000.

(3) Where the Chairman, a Vice-Chairman or a Member occupies an official residence beyond the permissible period, he shall be liable to pay license fee or panel rent, as the case may be, in accordance with rules and orders in force and he may be evicted.

By Order,

D.P. GAIROLA,
Principal Secretary.

चिकित्सा अनुभाग-3

31 मार्च, 2011 ई0

संख्या 246/XXVIII-3-2011-47/2008

प्रेषक,

डा० उमाकान्त पंवार,
सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड।

विषय— चिकित्सा विभाग के डेन्टल हाईजीनिस्ट को उच्चिकृत वेतनमान का लाभ पूर्व की तिथि से अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों के क्रम में परिपत्र संख्या 867/XXVII(7)/नौ०प्रति०/2011, दिनांक 08-03-2011 द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत डेन्टल हाईजीनिस्ट के वेतनमानों को उच्चिकृत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 271/XXVIII-3-2010-47/2008, दिनांक 15-04-2010 में

आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस श्रेणी के कार्मिकों को उच्चकृत वेतनमान ₹ 9300-34800, ग्रेड पे ₹ 4200 का लाभ दिनांक 01-01-2006 से प्राकल्पित आधार पर तथा वास्तविक लाभ उक्त शासनादेश दिनांक 15-04-2010 के अनुरूप अनुमन्य कराये जाने को श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त के फलस्वरूप पूर्व निर्गत उपरिल्लिखित शासनादेश दिनांक 15-04-2010 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या 2956/XXVII(7)/2011, दिनांक 17 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग-1

अधिसूचना

01 अप्रैल, 2011 ई0

संख्या 313/XIII-1/2011-1(101)2002-राज्यपाल, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 38 के उपखण्ड (5) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10, वर्ष 1987) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस विषय में पूर्व में जारी अधिसूचना को अवक्रमित करते हुए "उर्वरक के मिश्रणों" के श्रेणियों/विनिर्मिती के लिये राज्य सरकार को सलाह देने हेतु निम्नवत् एक राज्य उर्वरक समिति गठित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- | | |
|--|------------|
| (1) कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून | अध्यक्ष |
| (2) अधिष्ठाता, मृदा विज्ञान, गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर (ऊधमसिंह नगर) | सदस्य |
| (3) इण्डियन फार्मर फर्टिलाइजर कारपोरेशन (इफको) | सदस्य |
| (4) इण्डियन माइक्रोन्यूट्रीयेयन्ट्स फर्टिलाइजर मैनुफक्चर्स भवानी पक्ष, पूणे का प्रतिनिधि | सदस्य |
| (5) संयुक्त कृषि निदेशक (गुण नियंत्रण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून | सदस्य सचिव |

2. राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त समिति गुणवत्ता बनाये रखने के लिए विनिर्माण इकाई में प्रयोगशाला की स्थापना, नमूना लेने और विश्लेषण पद्धति तथा कृषकों की बेहतर सेवा हेतु व्यापारियों से गुणवत्ता के साथ चेतना उत्पन्न करने की प्रक्रिया विहित करने, राज्य सरकार को स्वयं के क्रिया-कलापों की छःमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने और एन0पी0के0 उर्वरक के मिश्रणों के विनिर्माण सूक्ष्म पोषक मिश्रणों और देशी दानेदार लघु उर्वरकों और उसके मिश्रणों के सम्बन्ध में कोई मामला, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उसे सौंपा जाय, पर सलाह देगी।

3. समिति समय-समय पर परामर्श देने के लिए ऐसे व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकती है, जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हों।

4. समिति का कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष होगा।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
सचिव।

कृषि एवं विपणन अनुभाग-2

अधिसूचना

20 अप्रैल, 2011 ई0

संख्या 239/XIII(2)/2011-156(01)/2001-राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 10 की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के नियम 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचित करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तारीख से कोई भी व्यक्ति प्रधान मण्डी स्थल, जसपुर (ऊधमसिंह नगर) में, जैसा शासकीय अधिसूचना संख्या 714/XIII-II/156(01)/2001, दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 में इस रूप में अधिसूचित है, विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के क्रय विक्रय के किसी भी सौदे के सन्दर्भ में नियत व्यापारिक परिचयों से भिन्न कोई व्यापारिक परिचय न तो आरोपित करेगा और न वसूल करेगा।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 239/XIII-II/2011-156(01)/2001, dated April 20, 2011 for general information :

NOTIFICATION

April 20, 2011

No. 239/XIII-II/2011-156(01)/2001—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 10 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (as applicable in the Uttarakhand) read with Rule 79 of Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965 (as applicable in the Uttarakhand), the Governor is pleased to notify that with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, no person shall levy charges or realize any trade charges in respect of any transaction either sale or purchase of the specified agricultural produce in the Principal Market yard, Jaspur (Udham Singh Nagar) declared as such in Government notification no. 714/XIII-II/156(01)/2001, Dated October 26, 2006.

By Order,

OM PRAKASH,
Secretary.

वित्त अनुभाग-8

अधिसूचना

20 अप्रैल, 2011 ई0

संख्या 462/2011/07(100)/XXVII(8)/08-मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की संस्तुति के क्रम में उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 54 की उपधारा (2)(क) एवं उपधारा (4)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल श्री रमेश चन्द्र कुक्रेती, निबन्धक, लोक सेवा अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा सदस्य, न्यायिक वाणिज्य कर अधिकरण, देहरादून पीठ, देहरादून को पूर्णरूपेण अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं सदस्य, न्यायिक, वाणिज्य कर अधिकरण, देहरादून पीठ, देहरादून के पद पर तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
सचिव।

चिकित्सा अनुभाग-2**कार्यालय-ज्ञाप**

05 मई, 2011 ई०

संख्या 532/XXVIII-2-2011-27/2004-महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 1प/रा०पु०/8/1./2001/2435, दिनांक 27-01-2011 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार उत्तराखण्ड पी०एम०एच०एस० संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत डा० सुरेश चन्द्र टम्टा, अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल निम्न तालिका में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित तिथि से अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्ति हो जायेंगे-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम/तैनाती का स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्त की तिथि
1.	डा० सुरेश चन्द्र टम्टा	अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल	01-01-1952	31-12-2011

डा० उमाकान्त पंवार,
सचिव।

चिकित्सा अनुभाग-3**विज्ञप्ति/प्रोन्नति**

10 मई, 2011 ई०

संख्या 434/XXVIII-3-2011-74/2007-कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, औषधि निरीक्षक वेतनक्रम ₹ 9300-34800, ग्रेड पे ₹ 4600 को वरिष्ठ औषधि निरीक्षक वेतनक्रम 15600-39100, ग्रेड पे ₹ 5400 के पद पर नितान्त अस्थायी रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ औपबन्धित आधार पर पदोन्नति प्रदान की जाती है कि यह पदोन्नति उ०प्र० एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य पारस्परिक स्थानान्तरण के आधार पर आवंटन के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या 79(एस०बी०)/2008 में पारित निर्णय दिनांक 26-07-2010 के सन्दर्भ में आवंटन पर लिये जाने वाले निर्णय के अधीन होगी।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री शर्मा की तैनाती अग्रिम आदेशों तक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उपलब्ध वरिष्ठ औषधि निरीक्षक के रिक्त पद के सापेक्ष की जाती है।

डा० उमाकान्त पंवार,
सचिव।

पशुपालन विभाग-1**कार्यालय ज्ञाप**

27 मई, 2011 ई०

संख्या 545/XV-1/2(6)/10-पशुपालन विभाग में पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1 वेतनमान रु० 15600-39100, ग्रेड पे-6600 के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के आधार पर निम्न पशुचिकित्सा अधिकारियों को पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1 वेतनमान रु० 15600-39100, ग्रेड पे-6600 में पदोन्नत किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र०सं०	पशुचिकित्साधिकारी का नाम
1.	डा० डी०सी० खुल्बे

2. उपरोक्त अधिकारियों को नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1 के पद पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है तथा अग्रिम आदेश तक वे अपने वर्तमान पद पर कार्य निर्वहन करते रहेंगे। उक्त अधिकारियों के पद स्थापना के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से,

विनोद फोनिया,
सचिव।

चिकित्सा अनुभाग-2

विज्ञप्ति / नियुक्ति

07 जून, 2011 ई0

संख्या 622/XXVIII-2-2011-92/2006-उत्तराखण्ड पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अन्तर्गत अपर निदेशक वेतनमान वेतन बैण्ड-4, सदृश वेतन बैण्ड/वेतनमान ₹ 37400-67000, ग्रेड पे ₹ 8900 के पद पर कार्यरत डा0 जगदीश चन्द्र दुर्गापाल, अपर निदेशक को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निदेशक के पद पर वेतनमान वेतन बैण्ड-4, सदृश वेतन बैण्ड/वेतनमान ₹ 37400-67000, ग्रेड पे ₹ 10000 में पदोन्नति प्रदान करते हुए 06 माह की विहित परिवीक्षा अवधि में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. डा0 जगदीश चन्द्र दुर्गापाल, निदेशक को सम्भागीय निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमायूँ मण्डल नैनीताल के पद पर तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

लघु सिंचाई अनुभाग

अधिसूचना / नियुक्ति

17 जून, 2011 ई0

संख्या 813/II-2011-01(12)/2005-उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य अभियन्त्रण सेवा परीक्षा, 2007 के आधार पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों में से निम्न अभ्यर्थियों को सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई (कृषि) वेतनमान ₹ 15600-39100, ग्रेड पे ₹ 5400 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन योगदान करने की तिथि से अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य की जाने वाली सुविधाएं देय होगी।

क्र0सं0	नाम/पिता का नाम	श्रेणी	पदस्थापना का स्थान
1.	श्री कृष्ण सिंह कन्याल पुत्र श्री हरक सिंह कन्याल	सामान्य	उपखण्ड धारी, जनपद नैनीताल
2.	श्री सुधाकर कुमार चक्रवर्ती पुत्र श्री जग्गू प्रसाद	सामान्य	उपखण्ड नौगांव, जनपद उत्तरकाशी
3.	श्री प्रशान्त कुमार	अनु0जाति	उपखण्ड डीडिहाट,

सम्बन्धित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी योगदान रिपोर्ट एक माह के अन्दर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई के कार्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा उन्हें निम्नवत् सूचनाएं एवं प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे, तदोपरान्त ही उनकी योगदान सूचना स्वीकार की जायेगी-

1. समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
3. एक से अधिक जीवित पत्नी न होने की घोषणा/शपथ-पत्र।
4. दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो उनके सम्बन्धी न हों, के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र।
5. शैक्षिक योग्यता, आयु एवं जाति से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति।

आज्ञा से,
ओम प्रकाश,
सचिव।

वित्त अनुभाग-9

अधिसूचना

28 जून, 2011 ई0

संख्या 393/XXVII-9-2010/स्टाम्प-09/2009-RTI-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22, वर्ष 2005) की धारा 5 व धारा 19 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल द्वारा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन तथा मनोरंजन कर विभाग के शासन स्तर हेतु निम्नलिखित लोक प्राधिकारी इकाई के सम्मुख अंकित लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के रूप में अधिसूचित/नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र0सं0	लोक प्राधिकारी इकाई	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1.	वित्त विभाग (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन तथा मनोरंजन कर)	श्री नन्दन सिंह बिष्ट, अनुभाग अधिकारी, वित्त अनुभाग-9	श्री प्रदीप सिंह रावत, उप सचिव, वित्त अनुभाग-9

2. उपर्युक्त नामित किये गये लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में उल्लिखित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के लिये पूर्णरूप से जिम्मेदार होंगे एवं इस कार्य हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन, भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

शासन की संदर्भगत अधिसूचना संख्या 836/XXVII-9-2010/स्टाम्प/2009-RTI, दिनांक 22 अक्टूबर, 2010 को इस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

आज्ञा से,
राधा रतूड़ी,
सचिव।

लघु सिंचाई अनुभाग

अधिसूचना/नियुक्ति

29 जून, 2011 ई0

संख्या 804/II-2011-01(12)/2005-उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य अभियन्त्रण सेवा परीक्षा, 2007 के आधार पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों में से निम्न अभ्यर्थियों को सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई (सिविल) वेतनमान स 15600-39100, ग्रेड पे स 5400 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन योगदान करने की तिथि से अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए दो वर्ष की परीक्षा पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य की जाने वाली सुविधाएं देय होगी।

क्र०सं०	नाम/पिता का नाम	श्रेणी	पदस्थापना का स्थान
1.	श्री अभिषेक खोलिया पुत्र श्री नन्द किशोर खोलिया	सामान्य	उपखण्ड चमोली, जनपद चमोली
2.	श्री दीपांकर भारती पुत्र श्री कलीराम	अनु०जाति	उपखण्ड रुद्रप्रयाग, जनपद रुद्रप्रयाग

सम्बन्धित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी योगदान रिपोर्ट एक माह के अन्दर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई के कार्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा उन्हें निम्नवत् सूचनाएं एवं प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे, तदोपरान्त ही उनकी योगदान सूचना स्वीकार की जायेगी—

1. समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
3. एक से अधिक जीवित पत्नी न होने की घोषणा/शपथ-पत्र।
4. दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो उनके सम्बन्धी न हों, के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र।
5. शैक्षिक योग्यता, आयु एवं जाति से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति।

आज्ञा से,
ओम प्रकाश,
सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 जुलाई, 2011 ई0 (श्रावण 08, 1933 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

May 24, 2011

No. 131/XIV/22/Admin.A/2008--Sri Vivek Srivastava, the then Civil Judge (Jr. Div.), Nainital, presently posted as Civil Judge (Jr. Div.), Narendra Nagar, Distt. Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 25-04-2011 to 04-05-2011.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

PRASHANT JOSHI,

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

May 24, 2011

No. 132/UHC/Admin.A/2011--In exercise of the powers conferred by Rule 27 (ii) of the Uttarakhand Higher Judicial Service Rules, 2004 and all other power enabling in this behalf, the Hon'ble Court is pleased to grant the Supertime Scale of ₹ 70,290-1,540-76,450 to the following Officers after Completing 03 years of continuous service in the Selection Grade of H.J.S. Cadre from the date mentioned against their names --

Sl. No.	Name of the Officer	Date of grant of Supertime Scale
1.	Sri Ramesh Chandra Kukreti	11-04-2011
2.	Sri Dinesh Prasad Gairola	21-04-2011

June 24, 2011

No. 149/UHC/Admin.A/2011--Smt. Meena Tiwari, District & Sessions Judge, Chamoli is transferred and posted as District & Sessions Judge, Nainital w.e.f. 01-07-2011 vice Sri Rood Deo Pandey on his superannuation on 30-06-2011

June 24, 2011

No. 150/UHC/Admin.A/2011--Sri Ashish Naithani, 3rd Addl. District & Sessions Judge, Udham Singh Nagar is transferred and posted as District & Sessions Judge, Chamoli w.e.f. 01-07-2011 vice Smt. Meena Tiwari.

By Order of the Court,

Sd/-

U.C. DHYANI,

Registrar General.

NOTIFICATION

July 05, 2011

No. 151/XIV-23/Admin.A/2008--Sri Sudhir Kumar Singh, Civil Judge (Jr. Div), Almora, is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 13-06-2011 to 25-06-2011 with permission to prefix 11-06-2011 and 12-06-2011 as 2nd Saturday and Sunday holidays and to suffix 26-06-2011 as Sunday.

July 06, 2011

No. 152/XIV/71/Admin.A/2003--Smt. Neena Agarwal, Civil Judge (Sr. Div), Roorkee, Distt. Hardwar, is hereby sanctioned earned leave for 06-06-2011 to 15-06-2011 with permission prefix 05-06-2011 as Sunday.

July 06, 2011

No. 153/XIV/79/Admin.A/2003--Smt. Neelam Ratra, Civil Judge (Sr. Div), Kotdwar, Distt. Pauri Garhwal, is hereby sanctioned Maternity (miscarriage) leave for 42 days (six weeks) w.e.f. 16-05-2011 to 26-06-2011, in terms of Subsidiary Rule 153 (2) Chapter XIII of F.H.B., Volume II (Parts 2-4).

July 06, 2011

No. 154/XIV/86/Admin.A/2003--Sri Mahesh Chandra Kaushiwa, Chief Judicial Magistrate, Rudraprayag, is hereby sanctioned earned leave for 20 days w.e.f. 06-06-2011 to 25-06-2011 with permission to prefix 05-06-2011 and to suffix 26-06-2011 as Sunday.

July 06, 2011

No. 155/XIV/95/Admin.A/2003--Km. Kusum, Civil Judge (Jr. Div), Udham Singh Nagar, is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 13-06-2011 to 25-06-2011 with permission to prefix 11-06-2011 and 12-06-2011 as 2nd Saturday and Sunday holidays and to suffix 26-06-2011 as Sunday.

July 14, 2011

No. 156/XIV/92/Admin.A/2003--Sri Om Kumar, Civil Judge (Sr. Div.), Pithoragarh, is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 13-06-2011 to 25-06-2011 with permission to prefix 11-06-2011 and 12-06-2011 as 2nd Saturday and Sunday holidays and to suffix 26-06-2011 as Sunday, for the purpose of L T C to hometown.

July 14, 2011

No. 157/XIV/82/Admin.A/2003--Smt. Pritu Sharma, Addl. Chief Judicial Magistrate, Haldwani, Distt. Nainital, is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 20-06-2011 to 02-07-2011 with permission to prefix 19-06-2011 and to suffix 03-07-2011 as Sunday

By Order of Hon'ble the Administrative Judge

Sd/-

PRASHANT JOSHI,

Registrar (Inspection)

**कार्यालय सम्मागीय परिवहन अधिकारी,
देहरादून सम्भाग, देहरादून**

26 मार्च, 2011 ई0

**श्री राजीव कुमार शर्मा पुत्र स्व0 कुन्दन लाल, 22 खुडबुड़ा, देहरादून की शिकायत के
सम्बन्ध में सुनवाई एवं निर्णय**

संख्या 2790/लाईसेन्स/2011-श्री अंकित ठाकुर पुत्र श्री मिथन सिंह, बादशाही बाग, घंघोड़ा, गढ़ीकैन्ट, देहरादून के नाम पर इस कार्यालय से अलग-अलग जन्म तिथियों के आधार पर दो चालन अनुज्ञप्तियां प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्री राजीव कुमार शर्मा द्वारा एक शिकायत दिनांक 20-09-2010 को इस कार्यालय को प्राप्त हुई। यह पाया गया कि श्री अंकित ठाकुर पुत्र श्री मिथन सिंह द्वारा इस कार्यालय में निम्नलिखित दो चालन अनुज्ञप्तियां प्राप्त की गयी है :-

1. UA-0720070009069 दिनांक 18-05-2007 को मो0 साईकिल हेतु जारी है। आवेदक की जन्म तिथि 07-07-1988 दर्शायी गयी है।
2. UA-0720100116027 दिनांक 22-06-2010 को मो0 साईकिल एवं हल्का मोटरयान (अव्यवसायिक) हेतु जारी है। आवेदक की जन्म तिथि 07-07-1991 दर्शायी गयी है।

उक्त सम्बन्ध में लाईसेन्सधारक श्री अंकित ठाकुर पुत्र श्री मिथन सिंह, बादशाही बाग, घंघोड़ा, गढ़ीकैन्ट, देहरादून को नोटिस संख्या 2386, दिनांक 11 अक्टूबर, 2010 जारी करते हुए निर्देश दिये गये थे कि वे एक सप्ताह के भीतर उक्त सम्बन्ध में मूल अभिलेखों व कार्यालय द्वारा जारी लाईसेन्स सहित उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। लाईसेन्सधारक कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। लाईसेन्सधारक द्वारा इस सम्बन्ध में लिखित उत्तर डाक के माध्यम से कार्यालय को प्रेषित किया गया जो कि दिनांक 29-10-2010 को प्राप्त हुआ। लाईसेन्सधारक द्वारा अपने उत्तर में कथन किया गया कि उनको दिनांक 18-05-2007 को जारी चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720070009069 हेतु आवेदन उनके पिता जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ने आर0टी0ओ0 में कार्यरत किसी व्यक्ति के माध्यम से दिया था तथा उक्त अनुज्ञप्ति पत्र बनाने के लिए उक्त व्यक्ति ने उनकी जन्म तिथि 07-07-1988 गलत दर्शायी थी, जबकि उनकी वास्तविक जन्म तिथि 07-07-1991 है। स्पष्ट है कि आवेदक आवेदन करने की तिथि को चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु अर्ह नहीं थे। उनके द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त की गयी है।

इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अपने उत्तर में यह भी कहा गया है कि पूर्व में जारी चालन अनुज्ञप्ति सं0 UA-0720070009069 खो जाने के कारण उनके द्वारा पुनः मई 2010 में चालन अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया गया, जिस पर उनको चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720100116027 जारी हुई है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में जन्म तिथि 07-07-1991 दर्शायी गयी है। आवेदक द्वारा पुनः चालन अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करते समय पूर्वधारित चालन अनुज्ञप्ति का विवरण एवं जन्म तिथि में भिन्नता का विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया। स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर/तथ्यों का छुपाकर चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त की गयी है।

निर्णय

शिकायतकर्ता उक्त सम्बन्ध में आज दिनांक 26-03-2011 को कार्यालय में उपस्थित हुए। मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-06(1) के अनुसार कोई व्यक्ति दो ड्राइविंग लाईसेन्स धारण नहीं कर सकता है। आवेदक द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है। लाईसेन्स धारक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। लाईसेन्स धारक उपस्थित नहीं हुए, उनके द्वारा अपना लिखित पक्ष कार्यालय को प्रेषित किया गया, जिसमें वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाये।

अतः, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(ड) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, डी0 सी0 पठोई, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) देहरादून कार्यालय द्वारा जारी लाईसेन्स संख्या UA-0720070009069 जो कि मोटर साईकिल हेतु जारी है तथा दिनांक 17-05-2027 तक वैध है तथा लाईसेन्स संख्या UA-0720100116027 जो कि मोटर साईकिल एवं हल्का मोटरयान (अव्यावसायिक) हेतु जारी है तथा दिनांक 21-06-2030 तक वैध है, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ। लाईसेन्स धारक यदि चाहें तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिवस की अवधि के भीतर आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, के समक्ष अपील कर सकते हैं।

अपीलीय अधिकारी का पता :

उप परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।
कार्यालय-परिवहन आयुक्त,
कुल्हान, सहस्रधारा रोड़,
देहरादून।

डी0 सी0 पठोई,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन) देहरादून।

कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

विज्ञप्ति

17 मार्च, 2011 ई0

पत्रांक 330/चार-6(2010-11)-उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग बैच, 2009) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों हेतु दिनांक 13 सितम्बर, 2010 से 30 अक्टूबर, 2010 की अवधि में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आयोजित की गयी विभागीय परीक्षा भाग-1 व भाग-2 में योगदान देने वाले निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित विषयों में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

क्र0सं0	नाम परिवीक्षाधीन अधिकारी	विषय
1.	डा0 राघव लंगर, आई0ए0एस0	A B C D E F G H I J
2.	श्री सी0 रविशंकर, आई0ए0एस0	A B C D E F G H I J

विषय संकेत :-

- A- आपराधिक वाद निर्णय लेखन
- B- राजस्व वाद निर्णय लेखन
- C- राजस्व नियम एवं अधिनियम तथा मू-सर्वेक्षण
- D- हिन्दी टिप्पणी एवं पत्र लेखन
- E- जिला प्रशासन

- F- लोक प्रशासन
- G- बजट एवं वित्तीय प्रक्रिया
- H- स्थानीय निकाय एवं विविध अधिनियम
- I- नियोजन एवं विकास
- J- कृषि एवं ग्राम्य विकास

ए0 एस0 नयाल,
अपर निदेशक।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 जुलाई, 2011 ई0 (श्रावण 08, 1933 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय पंचास्थानि चुनावालय, देहरादून

सूचना

01 अप्रैल, 2011 ई0

संख्या 01/पंचा0उप0निर्वा0/2011-राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या 2145/रा0नि0आ0 अनु0-2/989/2009, दिनांक 30-3-2011 के द्वारा सदस्य ग्राम पंचायत/प्रधान ग्राम पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों पर निर्वाचन/उप निर्वाचन कराये जाने हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है।

अतः, आयोग के उक्त अधिसूचना के क्रम में मैं, सचिन कुर्वे, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत), देहरादून एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि जनपद के सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत के रिक्त स्थानों पर निर्वाचन/उप निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित समय सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे :-

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
07-04-2011 एवं 08-04-2011 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 17.00 बजे तक)	11-04-2011 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	13-04-2011 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 13.00 बजे तक)	13-04-2011 (अपराह्न 13.30 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	24-04-2011 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 17.00 बजे तक)	27-04-2011 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

इस निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन हेतु निर्धारित एवं निर्देशित है। इन पदों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जाँच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी। प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य ग्राम पंचायत के रिक्त स्थानों का विकास खण्डवार विवरण संलग्न हैं, जिनका निर्वाचन/उप निर्वाचन कराया जाना है।

त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों/स्थानों का विवरण

36

उत्तराखण्ड गजट, 30 जुलाई, 2011 ई० (प्रावण 08, 1933 शक सम्वत्)

[भाग 3

जनपद देहरादून

क्र०	विकास खण्ड का नाम	पद का नाम	पद/स्थान का आरक्षण	ग्राम पंचायत का नाम	रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक	रिक्ति का दिनांक	रिक्ति का कारण
1.	यकराता	सदस्य ग्राम पंचायत	पि०व०महिला	1-भटाड़	03	सामान्य निर्वाचन-2008	नामांकन न होने का कारण
			पि०व०महिला	2-कूणा	06	सामान्य निर्वाचन-2008	नामांकन न होने का कारण
			अनु०जा०महिला	3-सुजऊ	06	सामान्य निर्वाचन-2008	नामांकन न होने का कारण
			पि०व०महिला		09	सामान्य निर्वाचन-2008	नामांकन न होने का कारण
			अनु०ज०जा०म०	4-बगूर	04	सामान्य निर्वाचन-2008	नामांकन न होने का कारण
			अनु०ज०जा०म०		05	सामान्य निर्वाचन-2008	नामांकन न होने का कारण
			पि०व०महिला	5-डिरनाड़	01	सामान्य निर्वाचन-2008	नामांकन न होने का कारण
			अनु०जा० महिला	6-छजाड़-हटाड़	06	सामान्य निर्वाचन-2008	नामांकन न होने का कारण
			अनु०ज०जा०म०	7-मटियाना	04	सामान्य निर्वाचन-2008	नामांकन न होने का कारण
			महिला	8-कोटीबावर	02	सामान्य निर्वाचन-2008	नामांकन न होने का कारण
			अनु०जा०महिला	9-मशक	02	सामान्य निर्वाचन-2008	नामांकन न होने का कारण
			अनु०जा०महिला	10-पेनुवा	05	सामान्य निर्वाचन-2008	नामांकन न होने का कारण
			अनु०ज०जा०म०	11-दावला	03	सामान्य निर्वाचन-2008	नामांकन न होने का कारण
			अनु०ज०जा०म०	12-जस्टा	05	सामान्य निर्वाचन-2008	नामांकन न होने का कारण
			अनु०जा०महिला	13-कोटा क्वानू	07	सामान्य निर्वाचन-2008	नामांकन न होने का कारण
			अनारक्षित	14-रायगी	01	सामान्य निर्वाचन-2008	नामांकन न होने का कारण
			अनु०ज०जा०	15-मेघाटू	03	सामान्य निर्वाचन-2008	नामांकन न होने का कारण

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	रायपुर	सदस्य ग्राम पंचायत	अनु०जा०जा०म० अनु०जा०महिला पि०व०महिला अनु०जा०महिला पि०व०महिला पि०व०महिला अनु०जा०महिला पि०व०महिला अनारक्षित	3-खाण्ड रायवाला 4-साहबनगर 1-कुड़ियाल 2-अखण्डवाली भिलंग 3-चालंग 4-भोपाल पानी 5-बडासी ग्रान्ट	06 03 06 01 04 02 06 06 08	सामान्य निर्वाचन-2008 सामान्य निर्वाचन-2008 सामान्य निर्वाचन-2008 सामान्य निर्वाचन-2008 सामान्य निर्वाचन-2008 सामान्य निर्वाचन-2008 सामान्य निर्वाचन-2008 सामान्य निर्वाचन-2008 सामान्य निर्वाचन-2008	नामांकन न होने का कारण नामांकन न होने का कारण नामांकन न होने का कारण नामांकन न होने का कारण नामांकन न होने का कारण नामांकन न होने का कारण नामांकन न होने का कारण नामांकन न होने का कारण नामांकन न होने का कारण

ह०/- अपठित,
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
पंचास्थानि-चुनावालय,
देहरादून।

ह०/- अपठित,
मुख्य विकास अधिकारी/
प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि-चुनावालय,
देहरादून।

सचिव कुर्वे,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत/स्था० नि०),
देहरादून।